रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248242 CG-DL-E-23082023-248242

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] No. 204] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2023/श्रावण 31, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2023/SHRAVANA 31, 1945

# खान मंत्रालय संकल्प

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2023

फा. सं. एम. I-4/1/2021-खान I.—केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम (प्रोग्रामिंग) बोर्ड (सीजीपीबी) और इसकी बारह सिमितियों के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 08.06.2009 की संकल्प संख्या 4(2)/97-एम-I, दिनांक 07.05.2013 की संख्या 4(6)/2013-एम. I, दिनांक 10.12.2018 की संख्या एम.I-4/I/2017-खान-I और दिनांक 17.05.2019 की संख्या एम.I-4/1/2019-खान I के माध्यम से मुख्य संकल्प में संशोधन करते हुए, इस मंत्रालय के दिनांक 12.03.2009 के संकल्प संख्या 4(2)97-एम. I (इसमें इसके पश्चात् इसे मुख्य संकल्प कहा गया है) और उसके बाद के संकल्पों के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा खान मंत्रालय में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है, अर्थात्:-

(i) मुख्य संकल्प में, पैरा 7 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"7. इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से, केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम (प्रोग्रामिंग) बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) सचिव, खान मंत्रालय -अध्यक्ष

(ख) अपर सचिव, खान मंत्रालय -सदस्य

(ग) महानिदेशक, भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण -सदस्य

(घ) संयुक्त सचिव (नीति) -सदस्य

(ङ) निम्नलिखित के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से कम न हों) -सदस्य (12)

5396 GI/2023 (1)

- (i) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (ii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- (iii) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- (iv) नागर विमानन मंत्रालय
- (v) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
- (vi) कोयला मंत्रालय
- (vii) इस्पात मंत्रालय
- (viii) रक्षा मंत्रालय
- (ix) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- (x) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- (xi) अंतरिक्ष विभाग
- (xii) परमाणु ऊर्जा विभाग
- (च) सलाहकार (खनिज) ,नीति आयोग

-सदस्य

- सदस्य (30)

- (छ) निम्नलिखित केंद्रीय संगठनों के प्रमुख:
  - (i) केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
  - (ii) केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)
  - (iii) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
  - (iv) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
  - (v) कोल इंडिया लिमिटेड और उसके (सीआईएल)संबंधित कार्यालय
  - (vi) सीएसआईआर केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान
  - (vii) केंद्रीय खान योजना एवं डिज़ाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआई)
  - (viii) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)
  - (ix) एनएलसी इंडिया लिमिटेड
  - (x) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद (आईएसएम)
  - (xi) राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
  - (xii) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालियन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी)
  - (xiii) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)
  - (xiv) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
  - (xv) केशव देव मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन(केडीएमआईपीई)
  - (xvi) परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर)
  - (xvii) भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई)
  - (xviii) भारतीय भूवैज्ञानिक सोसायटी
  - (xix) भारतीय खनन, भूवैज्ञानिक और धातुकर्म संस्थान (एमजीएमआई इंडिया)
  - (xx) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)
  - (xxi) सीएसआईआर- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी)
  - (xxii) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी)

- (xxiii) राष्ट्रीय ध्रवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर)
- (xxiv) सीएसआईआर- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (सीएसआईआर- एनआईओ)
- (xxv) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केंद्र

(जेएनएआरडीडीसी), नागपुर, महाराष्ट्र

- (xxvi) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी)
- (xxvii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
- (xxviii) एनएमडीसी लिमिटेड
- (xxix) मॉयल लिमिटेड
- (xxx) केआईओसीएल लिमिटेड
- (ज) राज्य सरकारों, खनन और भूविज्ञान/उद्योग/विभाग के सचिव (निदेशक, खनन एवं -सदस्य भूविज्ञान स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे)
- (झ) संगठनों से उद्योग प्रतिनिधि, अर्थात्:

-सदस्य (06)

- (i) भारतीय खनिज उद्योग संघ (फिमि)
- (ii) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
- (iii) टाटा स्टील
- (iv) रूंगटा माइंस
- (v) जियोमैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- (vi) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल)
- (ञ) अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) क्षेत्र, -सदस्य मानचित्र एवं प्रकाशन, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी
- (ट) अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, नीति सहायता प्रणाली-योजना एवं निगरानी, -सदस्य सचिव भारतीय भृवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)

अध्यक्ष भूविज्ञान से संबंधित किसी अन्य संगठन के एक विशेष प्रतिनिधि को बोर्ड की बैठक में विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में या बोर्ड की सभी बैठकों में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकता है।"

(ii) मुख्य संकल्प में, अनुबंध क के लिए, निम्नलिखित अनुबंध को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -"अनुबंध क

## समितियों का गठन और विचारार्थ विषय

# समिति I. लौह खनिज (लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट, आदि)

संयोजक: अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.), कोलकाता सदस्य सिचव: निदेशक, नीति सहायता प्रणाली, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.), कोलकाता सदस्य:

1. इस्पात मंत्रालय (निदेशक-तकनीकी स्तर)

- 2. खान मंत्रालय, निदेशक (नीति)
- 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (निदेशक स्तर)
- 4. डीएमजी, कर्नाटक सरकार
- 5. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
- 6. डीएमजी, गोवा सरकार
- 7. डीजीएम, राजस्थान सरकार
- 8. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
- 9. एमआरडी, मध्य प्रदेश सरकार
- 10. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
- 11. डीएमजी, झारखण्ड सरकार
- 12. महानिदेशक, ओडिशा सरकार
- 13. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
- 14. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
- 15. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को)
- 16. भारतीय खनिज उद्योग संघ (फिमि)
- 17. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी)
- 18. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई
- 19. क्षेत्रीय मिशन प्रमुख- II, जीएसआई (पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र)
- 20. राज्य इकाइयों के उप महानिदेशक; फेरस समूह जांच की मदों से संबद्ध जीएसआई के निदेशक; निदेशक, पीएसएस-पी एंड एम-2, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली स्थायी आमंत्रित:
  - i. एनएमडीसी लिमिटेड
  - ii. ओडिशा माइर्निंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी)
  - iii. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)
  - iv. मैंगनीज अयस्क (एमओआईएल) लिमिटेड (इंडिया)
  - v. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
  - vi. युनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा लिमिटेड
  - vii. इकोमेन लेबोरेटरीज प्रा लिमिटेड
  - viii. जेएसडब्ल्यू स्टील

# समिति II. कीमती धातुएँ और खनिज (सोना, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स, हीरा और कीमती पत्थर)

संयोजक: अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.), हैदराबाद सदस्य सचिव: निदेशक, नीति सहायता प्रणाली, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.), हैदराबाद

#### सदस्य:

- 1. निदेशक (खान IV), खान मंत्रालय
- 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के प्रतिनिधि
- 3. डीएमजी, कर्नाटक सरकार
- 4. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
- 5. डीजीएम, तमिलनाडु सरकार
- 6. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
- 7. एमआरडी, मध्य प्रदेश सरकार
- 8. डीएमजी, झारखण्ड सरकार
- 9. महानिदेशक, ओडिशा सरकार
- 10. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
- 11. डीजीएम, उत्तर प्रदेश सरकार
- 12. डीएमजी, राजस्थान सरकार
- 13. भारतीय खनिज उद्योग संघ (फिमि)
- 14. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
- 15. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
- 16. राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
- 17. जियो मैसूर सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
- 18. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी)
- 19. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई
- 20. क्षेत्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई (पूर्वी क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र)
- 21. राज्य इकाइयों के उप महानिदेशक; कीमती धातु और खनिज समूह की जांच से संबद्ध जीएसआई के निदेशक; निदेशक, पीएसएस-पीएंडएम-2, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली

#### स्थायी आमंत्रित:-

- i. हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लिमिटेड (एचजीएमएल)
- ii. रूंगटा माइंस प्रा. लिमिटेड
- iii. डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड
- iv. रामगढ माइनिंग एंड मिनरल्स प्रा. लिमिटेड
- v. एनएमडीसी लिमिटेड
- vi. आदित्य बिड़ला ग्रुप (एस्सेल माइनिंग)
- vii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद
- viii. सीएसआईआर-खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएमएमटी), भवनेश्वर, ओडिशा
- ix. माहेश्वरी माइनिंग प्रा. लिमिटेड (एमएमपीएल)
- x. जियोवेल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड

# xi. जेम्कोकाटी एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

# समिति III. अलौह और सामरिक खनिज (बेसमेटल, टिन, टंगस्टन, बॉक्साइट)

संयोजक: अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.), जयपुर सदस्य सिचव: निदेशक, नीति सहायता प्रणाली, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.), जयपुर सदस्य:

- 1. खान मंत्रालय, निदेशक (धातु-I)
- 2. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
- 3. डीएमजी, राजस्थान सरकार
- 4. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
- 5. डीजीएम, तमिलनाडु सरकार
- 6. डीएमजी, कर्नाटक सरकार
- 7. महानिदेशक, ओडिशा सरकार
- 8. डीजीएम, झारखण्ड सरकार
- 9. परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर)
- 10. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
- 11. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
- 12. जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी), नागपुर, महाराष्ट्र
- 13. ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी)
- 14. राष्टीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी)
- 15. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई
- 16. क्षेत्रीय मिशन प्रमुख- II, जीएसआई (पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र)
- 17. राज्य इकाइयों के उप महानिदेशक; सामरिक और अलौह जांच की मदों से संबद्ध जीएसआई के निदेशक; निदेशक, पीएसएस-पीएंडएम-2, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली

#### स्थायी आमंत्रित:-

- i. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ, हैदराबाद)
- ii. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)
- iii. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)
- iv. रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल, नई दिल्ली)
- v. हिंडाल्को
- vi. आईएमएमटी, भुवनेश्वर
- vii. आईआरईएल लिमिटेड (इंडिया), केरल
- viii. केरल दुर्लभ मृदा एवं खनिज लिमिटेड
- ix. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क)
- x. जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्रा लिमिटेड

- xi. जियोवेल सेवाएँ
- xii. ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्लू)
- xiii. सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र (सीएसईपी)
- xiv. हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (एचज़ेडएल)

## समिति IV: औद्योगिक और उर्वरक खनिज

संयोजक: अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), मध्य क्षेत्र (म.क्षे.), नागपुर सदस्य सिचव: निदेशक, नीति सहायता प्रणाली, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), मध्य क्षेत्र (म.क्षे.), नागपुर सदस्य:

- 1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
- 2. निदेशक, उर्वरक मंत्रालय
- 3. निदेशक, उद्योग विभाग
- 4. डीजीएम, राजस्थान सरकार
- 5. डीजीएम, उत्तर प्रदेश सरकार
- 6. सीजीएम, गुजरात सरकार
- 7. एमआरडी, मध्य प्रदेश सरकार
- 8. डीएमजी, मेघालय सरकार
- 9. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
- 10. डीजीएम, जम्मू और कश्मीर सरकार
- 11. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
- 12. डीएमजी, कर्नाटक सरकार
- 13. महानिदेशक, ओडिशा सरकार
- 14. भूवैज्ञानिक स्कंध, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
- 15. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
- 16. डीजीएम, असम सरकार
- 17. डीएमजी, तेलंगाना सरकार
- 18. उप महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश
- 19. डीजीएम, राजस्थान
- 20. डीजीएम, बिहार
- 21. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
- 22. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
- 23. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी)
- 24. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई
- 25. क्षेत्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई (दक्षिणी क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र)

26. राज्य इकाइयों (राजस्थान या मध्य प्रदेश) के उप महानिदेशक; औद्योगिक और उर्वरक खनिज समूह जांच की मदों से संबद्ध जीएसआई के निदेशक; निदेशक, पीएसएस-पीएंडएम-2, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली

## स्थायी आमंत्रित:-

- (i) सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधि ( एसीसी लिमिटेड)
- (ii) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
- (iii) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल)
- (iv) अल्ट्राटेक सीमेंट

# समिति V: ऊर्जा खनिज और संसाधन (कोयला, लिग्नाइट और भूतापीय)

संयोजकः उप महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन (एनईएनआर), एम-IIबी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), कोलकाता

सदस्य सचिव: निदेशक, एनईएनआर, एम-IIबी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), कोलकाता

### सदस्य:

- 1. कोयला मंत्रालय (निदेशक-तकनीकी स्तर)
- 2. खान मंत्रालय (निदेशक-तकनीकी)
- 3. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (निदेशक-तकनीकी स्तर)
- 4. नीति आयोग (सलाहकार/संयुक्त सलाहकार: विद्युत एवं ऊर्जा)
- 5. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
- 6. सीजीएम, गुजरात सरकार
- 7. डीजीएम, राजस्थान सरकार
- 8. डीजीएम, छत्तीसगढ़ सरकार
- 9. डीएमजी, झारखण्ड सरकार
- 10. डीएमएम, पश्चिम बंगाल सरकार
- 11. महानिदेशक. ओडिशा सरकार
- 12. एमआरडी, मध्य प्रदेश सरकार
- 13. डीजीएम, तमिलनाडु सरकार
- 14. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
- 15. डीजीएम, उत्तर प्रदेश सरकार
- 16. डीएमजी, तेलंगाना सरकार
- 17. डीजीएम, असम सरकार
- 18. डीएमजी, मेघालय सरकार
- 19. डीजीएम, नागालैंड सरकार
- 20. डीजीएम, अरुणाचल प्रदेश सरकार
- 21. डीजीएमआर, मिज़ोरम सरकार
- 22. महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन

- 23. सीएसआईआर-एनजीआरआई
- 24. एनएलसी इंडिया लिमिटेड
- 25. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
- 26. सीआईएल (सीएमपीडीआईएल, रांची)
- 27. द सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)
- 28. सीएसआईआर-सीआईएमएफआर
- 29. ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी)
- 30. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी)
- 31. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय मुख्यालय, जीएसआई
- 32. उप महानिदेशक, नीति सहायता प्रणाली योजना एवं निगरानी, जीएसआई
- 33. उप महानिदेशक, सेंट्रल केमिकल लैब, केन्द्रीय मुख्यालय, जीएसआई
- 34. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई
- 35. क्षेत्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई (उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र)
- 36. ऊर्जा खनिज और संसाधन (कोयला, लिग्नाइट और थर्मल) से संबद्ध जीएसआई के निदेशक; निदेशक, पीएसएस-पीएंडएम-2, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली स्थायी आमंत्रित:-
  - (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
  - (ii) टाटा स्टील
  - (iii) एनटीपीसी लिमिटेड
  - (iv) सीएसआईआर,एनएमएल- जमशेदपुर
  - (v) भारतीय खनन, भूविज्ञान और धातुकर्म संस्थान (एमजीएमआई)
  - (vi) अदानी एंटरप्राइजेज
  - (vii) जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

# खनिजों के लिए सीजीपीबी समितियों के लिए विचारार्थ विषय (समिति-I से समिति-V)

समिति-I: लौह खनिज, समिति-II: बहुमूल्य धातुएं और खनिज, समिति-III: अलौह और सामरिक खनिज, समिति-IV: औद्योगिक और उर्वरक खनिज तथा समिति-V: सीजीपीबी की ऊर्जा खनिज एवं संसाधन समितियों का निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ पुनर्गठन किया गया:-

- 1. राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय, विस्तृत और संवर्धनात्मक गवेषण के लिए वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करना।
- 2. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित संवर्धनात्मक गवेषण योजनाओं के बजट के उपयोग के साथ-साथ चल रहे कार्यक्रमों सहित समिति के गतिविधि क्षेत्र से संबंधित अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना।
- 3. निर्धारित योजना उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार सरकारी, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा गवेषण कार्य का समन्वय करना।
- गवेषण में केंद्रीय और राज्य संगठनों तथा सार्वजिनक-निजी भागीदारी के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना।

- 5. ज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगतिशील प्रगति को ध्यान में रखते हुए स्टेटस पेपर, दीर्घकालिक/अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करना, अंतिम-उपयोगकर्ताओं के विनिर्देशों के मैनुअल को अद्यतन करना।
- 6. केंद्रीय, राज्य और निजी एजेंसियों को शामिल करते हुए सभी क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण का डेटाबेस (स्थिति मानचित्र सहित) तैयार करना और अद्यतन करना।
- 7. डेटा साझाकरण और प्रसार के लिए कार्यप्रणाली तैयार करना और एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- 8. वैश्विक मानकों के अनुरूप वैज्ञानिक खनन, अयस्क ड्रेसिंग और सज्जीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाकर देश की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खनिजों के संरक्षण और इष्टतम उपयोग पर सरकार को सलाह देना।
- 9. नियम के अनुसार, क्षेत्रीय गवेषण में लगे संयुक्त लाइसेंस/खनन पट्टा/गवेषण लाइसेंस धारकों और अन्य ऐजेंसियों द्वारा खनिज गवेषण रिर्पोटिंग टैम्पलेट (एमईआरटी) के अनुसार राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा कोष (एनजीडीआर) में डेटा फाइलिंग सुनिश्चित करना और एक चिह्नित प्रणाली के माध्यम से लॉक-इन अविध के बाद सार्वजिनक डोमेन में इसकी उपलब्धता की निगरानी करना।
- 10. खनिज क्षेत्र में गवेषण तकनीकों, क्षेत्र/नमूना उपकरणों के आधुनिकीकरण और सज्जीकरण से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यों को प्राथमिकता देना।
- 11. केंद्रीय और राज्य संगठनों के कार्मिकों को मजबूत करने के लिए मानव संसाधन विकास और कार्मिकों के प्रशिक्षण पर सरकार को सलाह देना।

समिति के पास समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल करने का अधिकार होगा।

# समिति VI: समुद्री भूविज्ञान एवं गवेषण और तटीय भूविज्ञान

**संयोजक:** उप. महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) , समुद्री एवं तटीय सर्वेक्षण प्रभाग (एमसीएसडी), मंगलुरु

**सदस्य सचिव:** निदेशक, नीति सहायता प्रणाली (पीएसएस), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), समुद्री और तटीय सर्वेक्षण प्रभाग (एमसीएसडी), मंगल्रु

#### सदस्य:

- 1. खान मंत्रालय, नई दिल्ली (निदेशक तकनीकी स्तर)
- 2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली (निदेशक तकनीकी स्तर)
- 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), नई दिल्ली (निदेशक तकनीकी स्तर)
- 4. भारतीय खान ब्यूरो ,(आईबीएम)नागपुर
- 5. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, नई दिल्ली
- 6. महानिदेशक, ओडिशा सरकार
- 7. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
- 8. डीजीएम, तमिलनाडु सरकार
- 9. डीएमजी ,केरल सरकार
- 10. डीएमजी ,कर्नाटक सरकार
- 11. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
- 12. डीएमजी गोवा सरकार
- 13. सीजीएम, गुजरात सरकार
- 14. राष्ट्रीय ध्रवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा
- 15. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा
- 16. परमाण् खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर), हैदराबाद

- 17. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख आईए-, जीएसआई
- 18. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई
- 19. राज्य इकाइयों के उप महानिदेशक; समुद्री भूविज्ञान एवं गवेषण और तटीय भूविज्ञान पर जांच से जुड़े जीएसआई के निदेशक; निदेशक, पीएसएसपी-&एम-1, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली

## स्थायी आमंत्रित-:

- i. भारतीय नौवाहन निगम लिमिटेड, (एससीआई), मुंबई
- ii. भारतीय नौसेना (आईएन), नई दिल्ली
- iii. राष्ट्रीय भौतिक समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला ,(एनपीओएल)कोचीन
- iv. राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय ,(एनएचओ)देहरादून
- v. अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ,(एसएसी)अहमदाबाद
- vi. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद
- vii. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ,(एनआईओटी)चेन्नई
- viii.तटीय कटाव निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
- ix. एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन ,(आईसीएमएएम)चेन्नई
- x. भूसमुद्री- समाधान

# सीजीपीबी की समिति VI (समुद्री) के लिए विचारार्थ विषय

- 1. राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना।
- 2. चल रही परियोजनाओं सहित समिति के गतिविधि क्षेत्र से संबंधित अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना।
- 3. योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में जीएसआई और अन्य संगठनों के विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों पर ठोस सुझाव देना।
- 4. विभिन्न कार्य के लिए सौंपी गई प्राथमिकताओं में, यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन की सिफारिश करना। खान मंत्रालय और एमओईएस के बीच प्राथमिकताओं और साझा जिम्मेवारी को (क) अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और खिनजकरण के अनुसार आवंटित गहरे समुद्र क्षेत्रों में भी व्यवस्थित समुद्र तल मानिचत्रण और क्षेत्रीय अपतटीय खिनज गवेषण और (ख) भिवष्य में विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) का व्यवस्थित समुद्र तल मानिचत्रण के संबंध में परिभाषित किया जाना है।
- 5. तटीय आपदाओं के लिए उपचारात्मक उपायों की योजना बनाने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करने की दृष्टि से तटीय आकृति विज्ञान के वर्गीकरण को अद्यतन करना और डेटा का डिजिटलीकरण करना।
- 6. अपतटीय डेटा की रणनीतिक और वर्गीकृत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों को डेटा प्रसार के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सृजित अपतटीय डेटा के पुनर्वर्गीकरण का प्रस्ताव करना और सदस्य संगठनों के साथ-साथ सार्वजनिक डोमेन में इसके आदान-प्रदान के तौर-तरीकों पर काम करना।
- 7. एनएमपी, 2019 में नए विकास के मद्देनजर स्थिति दस्तावेज, दीर्घकालिक/अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करना और अंतिम उपयोगकर्ता विनिर्देश तैयार करना।
- 8. समुद्री भूविज्ञान में ज्ञान के विकास के लिए जीएसआई और अन्य सदस्य संगठनों तथा भारत और विदेशों में विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों के बीच सहयोगात्मक कार्यक्रम पर सुझाव देना।
- 9. समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर विशेष गतिविधि क्षेत्र जैसे तटीय भूविज्ञान, भू-तकनीकी पैरामीटरों, पर्यावरण मूल्यांकन आदि से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण किसी भी मामले पर सलाह देना।
- 10. समिति के पास समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य संस्थाओं को आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल करने का अधिकार होगा।

# समिति VII: हवाई सर्वेक्षण और सुदूर संवेदन

**संयोजक:** उप महानिदेशक और विभागाध्यक्ष, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), सुदूर संवेदन और हवाई सर्वेक्षण (आरएसएएस), बेंगलुरु

**सदस्य सचिव:** उप महानिदेशक और विभागाध्यक्ष , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), सुदूर संवेदन और हवाई सर्वेक्षण (आरएसएएस), बेंगलुरु

#### सदस्य:

- 1. खान मंत्रालय, नई दिल्ली (निदेशक तकनीकी स्तर)
- 2. रक्षा मंत्रालय (निदेशक तकनीकी स्तर)
- 3. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
- 4. डीजीएम, मध्य प्रदेश सरकार
- 5. महानिदेशक. ओडिशा सरकार
- 6. डीएमजी, राजस्थान सरकार
- 7. डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार
- 8. डीएमजी, कर्नाटक सरकार
- 9. डीजीएम, छत्तीसगढ सरकार
- 10. डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार
- 11. सीजीएम, गुजरात सरकार
- 12. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी)
- 13. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
- 14. परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर)
- 15. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
- 16. महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच), नई दिल्ली
- 17. राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
- 18. सभी क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केंद्र (आरआरएससी-इसरो)
- 19. ओडिशा खनन निगम (ओएमसी)
- 20. हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लिमिटेड (एचजीएमएल)
- 21. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
- 22. यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल)
- 23. मेसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, तेलंगाना
- 24. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी)
- 25. क्द्रेम्ख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बेंगल्रु
- 26. सीएमपीडीआई, रांची
- 27. एक्सियम एक्सप्लोरेशन ग्रुप लिमिटेड
- 28. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-।बी, जीएसआई
- 29. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई
- 30. क्षेत्रीय मिशन प्रमुख-I, जीएसआई (पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र)
- 31. राज्य इकाइयों के उप महानिदेशक; हवाई सर्वेक्षण और सुदूर संवेदन पर जांच से जुड़े जीएसआई के निदेशक; निदेशक (पीजीआरएस); निदेशक, पीएसएस-पीएंडएम-1, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली।

#### स्थायी आमंत्रित-:

- i. नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए)
- ii. भारतीय भूवैज्ञानिक समिति
- iii. भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ,(आईआईआरएस)देहरादून
- iv. कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्य (सुदूर संवेदन केंद्र)
- v. परियोजना समन्वयक, एएसआरएस ग्रुप (एएमडी)
- vi. मैक फर इंडिया
- vii. सैंडर्स जियोफिजिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

# सीजीपीबी की समिति VII (हवाई सर्वेक्षण और सुदूर संवेदन) के लिए विचारार्थ विषय

- 1. राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना।
- 2. समिति के गतिविधि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संगठनों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना।
- 3. योजना उद्देश्यों के संदर्भ में जीएसआई और अन्य संगठनों के चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर ठोस सुझाव देना।
- 4. भूवैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जानकारी का कम से कम उपयोग करने के लिए डेटाबेस साझा करने और अनुप्रयोग तैयार करने की दृष्टि से विभिन्न संगठनों के बीच आपसी संपर्क और सहयोग विकसित करना।
- 5. हवाई भूभौतिकीय डेटा और मानचित्रों के प्रसार को बढ़ावा देना और हवाई भूभौतिकीय डेटा साझा करने में प्रतिबंध हटाने के तरीकों का पता लगाना या समय-समय पर आवश्यक उपयुक्त उपाय सुझाना।
- 6. वायुजनित और हेलिबोर्न सुदूर संवेदन में प्रौद्योगिकीय विकास की समीक्षा और निगरानी करना और हाइपरस्पेक्ट्रल और गुरुत्वाकर्षण मानचित्रण सहित सर्वेक्षण और मानचित्रण हेतु अपनाने के लिए नई और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर सुझाव देना।
- 7. गवेषण लाइसेंस (ईएल) के माध्यम से प्राप्त डेटा के अधिग्रहण, प्रसंस्करण, उपयोग, संग्रह और प्रकाशन के प्रचलित नियमों/प्रतिबंधों की समीक्षा करना।
- 8. सिमिति के आवश्यक समझे जाने पर किसी भी संबंधित मामले पर सरकार को सलाह देना।
  सिमिति के पास सिमिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल करने का अधिकार होगा।

# समिति VIII: पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) का भूविज्ञान और खनिज संसाधन

संयोजक: अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), शिलांग सदस्य सचिव: निदेशक, नीति सहायता प्रणाली (पीएसएस), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), शिलांग

#### सदस्य:

- 1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय
- 2. सलाहकार (तकनीकी कार्यक्रम योजना समन्वय), खान मंत्रालय
- 3. नीति आयोग, भारत सरकार (सलाहकार-खान) के प्रतिनिधि
- 4. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि

- 5. पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि
- 6. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
- 7. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
- 9. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)
- 10. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
- 11. परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर)
- 12. डीजीएम, अरुणाचल प्रदेश सरकार
- 13. डीजीएम, असम सरकार
- 14. डीसीआई, मणिपुर सरकार
- 15. डीएमजी, मेघालय सरकार
- 16. डीजीएमआर, मिज़ोरम सरकार
- 17. डीजीएम, नागालैंड सरकार
- 18. डीआईसी, त्रिपुरा सरकार
- 19. डीएमएमजी, सिक्किम सरकार
- 20. टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, टाटानगर
- 21. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)
- 22. उप महानिदेशक, जीएसआई प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद
- 23. उप महानिदेशक, जीएसआई, एनईएनआर, एम-आईआईबी, जीएसआई, कोलकाता
- 24. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई
- 25. क्षेत्रीय मिशन प्रमुख-II, जीएसआई, एनईआर
- 26. राज्य इकाइयों के उप महानिदेशक; एनईआर के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों की जांच से जुड़े जीएसआई के निदेशक; निदेशक, पीएसएस-पी एंड एम-2, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली

## स्थायी आमंत्रित:-

- i. डोनर, भारत सरकार (निदेशक स्तर) के प्रतिनिधि
- ii. एनईसी (सलाहकार, खनिज)
- iii. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
- iv. सीमा सड़क संगठन
- v. ऑयल इंडिया लिमिटेड (आयल)
- vi. एनएचपीसी लिमिटेड
- vii. एनटीपीसी लिमिटेड
- viii. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको)
- ix. नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (तत्कालीन आरआरएल), जोरहाट
- x. भूविज्ञान विभाग, नागालैंड विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि
- xi. भूविज्ञान विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि
- xii. भूविज्ञान विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि
- xiii.भूविज्ञान विभाग, डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि

xiv. भूविज्ञान विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि

xv. भविज्ञान विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर से प्रतिनिधि

xvi.भूविज्ञान विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक से प्रतिनिधि

xvii. नॉर्थईस्टर्न हिल यूनिवसिटी, शिलांग

xviii. आईआईटी, गुवाहाटी

xix. लाफार्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड

xx. उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे

xxi. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)

xxii. नॉर्थ ईस्टर्न कोल लिमिटेड (केवल सीआईएल की इकाई)

xxiii. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)

xxiv. कोल इंडिया लिमिटेड

xxv. स्टार सीमेंट

# सीजीपीबी की समिति VIII (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के लिए विचारार्थ विषय

- 1. क्षेत्रीय स्तर पर वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करना।
- 2. समिति भूविज्ञान गतिविधि के क्षेत्र में सभी प्रतिभागियों (सरकारी, सार्वजनिक, निजी, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं विकास संस्थान आदि) के लिए एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगी।
- 3. खनिज संसाधनों के मानचित्रण, गवेषण और दोहन के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के विभिन्न हितधारकों द्वारा पूर्वोत्तर में पृथ्वी विज्ञान से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी और समन्वय करना।
- 4. प्राकृतिक और मानवजनित दोनों खतरों के संदर्भ में क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना।
- 5. एनईआर देश का जलविद्युत भंडार गृह है और इसके विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों संगठन लगे हुए हैं, समिति विशेष रूप से जल संसाधन विकास पर भूवैज्ञानिक आश्चर्य और इंजीनियरिंग समाधानों के लिए निर्देशित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श/समाधान करने के लिए एक आम मंच के रूप में कार्य करेगी।
- 6. सौपी गयी विभिन्न कार्य मदों की प्राथमिकताओं में, यदि आवश्यक हो, परिवर्तन की सिफारिश करना।
- 7. विभिन्न आकस्मिक मुद्दों, दीर्घकालिक/अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाओं पर स्थिति शोध पत्र तैयार करना।
- 8. समिति के पास समिति के सार्थक विचार विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य-संस्थानों को आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल करने का अधिकार होगा।

# समिति IX: भूवैज्ञानिक गवेषण (भू-तकनीकी गवेषण, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय भूविज्ञान, उथली उपसतह भूविज्ञान और उपसतह जल विज्ञान)

संयोजक: अपर महानिदेशक / उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), उत्तरी क्षेत्र (एनआर), लखनऊ सदस्य सचिव: निदेशक, , नीति सहायता प्रणाली (पीएसएस), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.), लखनऊ

#### सदस्य :

- 1. खान मंत्रालय , (निदेशक तकनीकी )
- 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- 3. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली
- 4. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), इसरो
- 5. डीजीएम, जम्मू एवं कश्मीर सरकार

- 6. भूवैज्ञानिक स्कंध , उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
- 7. भूविज्ञान एवं खनन इकाई, उत्तराखंड सरकार
- पूर्वोत्तर राज्यों के डीजीएम
- 9. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर
- 10. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
- 11. राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-IV, जीएसआई
- 12. क्षेत्रीय मिशन प्रमुख-IV, जीएसआई (उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र)
- 13. भू-वैज्ञानिक जांच (भू-तकनीकी जांच, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय भूविज्ञान, उथला उपसतह भूविज्ञान और उपसतह जल विज्ञान) से जुड़े जीएसआई के उप महानिदेशक और निदेशक; निदेशक, पीएसएस-पी एंड एम-4, जीएसआई, केंद्रीय मुख्यालय , कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली

# स्थायी आमंत्रित:-

- i राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली
- ii राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की
- iii केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)
- iv राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी)
- v एन डब्ल्यू डी ए
- vi जी.बी.पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोडा
- vii केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- vii हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (एसएएसई), चंडीगढ़
- ix सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी कानपुर
- x भूकंपीय अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर
- xi एसडीएम/आरसी, जम्मू एवं कश्मीर सरकार
- xii एसडीएम/आरसी, हिमाचल प्रदेश सरकार
- xiii एसडीएम/आरसी, उत्तराखंड सरकार
- xiv एसडीएम/आरसी, पूर्वोत्तर राज्य की सरकार
- xv राष्ट्रीय रॉक यांत्रिकी संस्थान (एनआईआरएम)
- xvi राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)

# सीजीपीबी की समिति IX (भूवैज्ञानिक जांच) के लिए विचारार्थ विषय

- 1. राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना।
- 2. प्राकृतिक खतरों से उत्पन्न होने वाले सामाजिक मुद्दों पर समय-समय पर सरकार को सलाह देना और पुनर्वास सहित संभावित निवारक/शमन उपाय सुझाना।
- 3. न केवल भूस्खलन और भूकंप संबंधी अपितु आर्सेनिक, फ्लोरीन प्रदूषण जैसे भू-स्थानिक आयाम वाले अन्य सार्वजनिक-स्वास्थ्य और सार्वजनिक हित के मुद्दों संबंधी मापदंडों पर बड़ी संख्या में व्यवस्थित रूप से (जहां स्थानिक आधार पर संभव हो) डेटा की निगरानी और संग्रह करना।

- 4. स्पेस एप्लिकेशन मैनेजमैंट सिस्टम (पीसी- सेम्स) योजना समिति के तहत भूविज्ञान स्थायी समिति (एससी- जी) सिहत जलवायु परिवर्तन पर पीएम समिति को शामिल करते हुए विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना और भविष्य में काम के लिए उनके प्रस्तावों का आकलन करना और समिति के दायरे में भूवैज्ञानिक डोमेन में भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई के लिए गैप एरियाज की पहचान करना।
- 5. मृदा प्रणाली और उसके संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए भू-पर्यावरण और प्राकृतिक जोखिम वाले डोमेन में अत्याधुनिक और अनुसंधान के उपयोग को बढ़ावा देना।
- 6. प्राकृतिक जोखिमों सिंहत विभिन्न भूवैज्ञानिक संबंधित घटनाओं के संबंध में योजना, प्रबंधन, रोकथाम आदि के लिए जीआईएस एप्लिकेशन विकसित करने में सहायता हेतु स्थानिक डेटा सिंहत प्रासंगिक डेटा सेट के एकीकरण को सक्षम बनाना।
- 7. विशेष गतिविधि डोमेन से संबंधित किसी अन्य अत्यावश्यक मामले पर जैसा समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, सीजीपीबी को सलाह देना ।
- 8. इस समिति के पास विशेष विषय वस्तु पर छोटे समूहों जिनके पास विशिष्ट एजेंडा हो, की बैठकें बुलाने का अधिकार है।
- 9. यह समिति सार्थक विचार-विमर्श के लिए जब भी आवश्यक हो, अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल कर सकती है।

# समिति X: मौलिक और बहुविषयक भूविज्ञान

संयोजक: अपर/उप महानिदेशक एवं राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-IV, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), कोलकाता सदस्य सचिव: निदेशक, एम-IV, राष्ट्रीय भूविज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र (एनसीईजीआर), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), कोलकाता

#### सदस्य :

- 1. निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय, नई दिल्ली
- 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि
- 3. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून
- 4. राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
- 5. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून
- 6. भारतीय खान ब्यूरो के प्रतिनिधि
- 7. परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के प्रतिनिधि
- 8. क्षेत्रीय मिशन प्रमुख-IV, जीएसआई (उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र)
- 9. मिशन-IV प्रयोगशालाओं, मौलिक भूविज्ञान पर कार्यक्रमों से जुड़े जीएसआई के उपमहानिदेशक और निदेशक; उप. महानिदेशक, प्रशिक्षण संस्थान; निदेशक, पीएसएस-पी एंड एम-4, जीएसआई, मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली

## स्थायी आमंत्रित:-

सीएसआईआर के प्रतिनिधि
 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, दिल्ली
 भूविज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि
 भृविज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि

भविज्ञान विभाग, अन्ना विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि ٧ भूविज्ञान विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि νi भविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि vii भूविज्ञान विभाग एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि vii भविज्ञान विभाग, मैसर विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि ix भविज्ञान विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि Х आईआईटी (खड़गपुर, मुंबई, रूड़की) से प्रतिनिधि χi पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र. तिरुवनंतपुरम से प्रतिनिधि xii रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल, हैदराबाद) से प्रतिनिधि xiii एनसीईएमपी, इलाहाबाद से प्रतिनिधि xiv बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ से प्रतिनिधि χV इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड एप्लाइड जियोलॉजी के प्रतिनिधि χvi एनईईआरआई से प्रतिनिधि xvii सीजीडब्ल्यूबी के प्रतिनिधि xviii भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रतिनिधि xix भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रतिनिधि XX भविज्ञान विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि xxi राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि xxii भूविज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे से प्रतिनिधि xxiii पृथ्वी विज्ञान आईआईएसईआर कोलकाता से प्रतिनिधि xxiv भवैज्ञानिक अध्ययन इकाई भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रतिनिधि XXV हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) xxvi जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एंव डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी) xxvii xxviii मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)

# सीजीपीबी की समिति-X (मौलिक और बहुविषयक भूविज्ञान) के लिए विचारार्थ विषय

- मौलिक और अनुप्रयुक्त भूविज्ञान (भूविज्ञान, भूभौतिकी, भूरसायन, भूविज्ञान) के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा और प्राथमिकता देना।
- भूपर्पटी और स्थलमंडल में भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, पृथ्वी के उद्भव और खनिजों के स्थानीयकरण आदि की बेहतर समझ को प्रोत्साहित करना।
- भूविज्ञान में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना और भूवैज्ञानिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके विशेष रूप से उच्चतर स्तर पर सिफारिशें करना जिससे भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा के पूल क्षेत्र में सुधार किया जा सके।
- 4. भूवैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित नीति की समीक्षा करना और अनुसंधान के बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण आदि में सुधार करने के लिए सिफारिशें करना; और क्षेत्र प्रथाओं और मौलिक अनुसंधान के बीच बेहतर आपसी समन्वय सुनिश्चित करना।

- 5. इंस्ट्र्मेंटेशन (विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक) और कार्यप्रणाली में वैश्विक तकनीकी प्रगति की लगातार समीक्षा करना और प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की सिफारिश करना।
- 6. इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न संगठनों के पास उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधाओं को साझा करने की सुविधा और समन्वय करना।
- 7. खिनज अन्वेषण और खनन में नई और कुशल तकनीक विकसित करने, नए खिनज संसाधनों का पता लगाने, मूल्यवर्धन, अधिकतम उपयोग और मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य को बढ़ावा देना।
- 8 मानक संदर्भ सामग्री तैयार करने में विभिन्न संगठनों की भागीदारी।
- 9. फील्ड और प्रयोगशाला तकनीकों दोनों में मौजूदा किमयों के लिए प्रशिक्षण या अन्य ज्ञान अधिग्रहण उपायों द्वारा राज्यों और केंद्रीय संस्थानों के भीतर भूवैज्ञानिक ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद करना और भविष्य के लिए ऐसे ज्ञानधारक किमयों के दलों को सुझाव देना।
- 10. विभिन्न संगठनों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक गतिविधि डोमेन और कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- 11. क्यूरेटोरियल, भूवैज्ञानिक और रासायनिक अध्ययन और प्रदर्शनी और प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए पृथ्वी विज्ञान के नमूनों का संग्रह, रखरखाव, संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण।

# समिति XI: भूसूचना विज्ञान और डेटा प्रबंधन

संयोजक: अपर/उप. महानिदेशक एवं राष्ट्रीय मिशन प्रमुख-III, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ( जीएसआई), कोलकाता सदस्य सचिव: निदेशक (टीसी), मिशन-III, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ( जीएसआई), कोलकाता

#### सदस्य:

- 1. निदेशक(तकनीकी), खान मंत्रालय
- 2. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
- मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल)
- 4. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस)
- 5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) (भू-स्थानिक नीतियों और मुद्दों से संबंधित )
- परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर)
- 7. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के भूविज्ञान और खनन निदेशालय
- 8. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
- 9. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई)
- 10. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी)
- 11. राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई)
- 12. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
- 13. राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा भंडार के (ओसीबीआईएस) और ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेशन सिस्टम (एनजीडीआर) प्रभारी डीडीजी
- 14. भूसूचना विज्ञान और डेटा प्रबंधन-, एनजीडीआर कार्यक्रमों से जुड़े जीएसआई के डीडीजी और निदेशक; निदेशक पीएसएस-पी एंड एम-3, जीएसआई, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता; और निदेशक, सीजीपीबी सचिवालय, डीजीसीओ, नई दिल्ली

स्थायी आमंत्रित :-

- i. जीआईएस से संबंधित डीडीजी (एनआईसी)
- ii. तकनीकी निदेशक (एनआईसी), खान मंत्रालय
- iii. एएमडी (एनआईसी)
- iv. सिचव (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा नामित किए जाने वालें प्रत्येक राज्य के एक प्रतिनिधि
- v. राष्टीय स्थानिक डेटा अवसंरचना (एनएसडीआई)
- vi. राष्ट्रीय भ्-स्थानिक कार्यक्रम प्रभाग (तत्कालीन एनआरडीएमएस)
- vii. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)
- viii. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
- ix. गृह मंत्रालय (एमएचए)
- x. भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन)
- xi. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (एमआरएसएसी)

# सीजीपीबी की समिति-XI (भूसूचना विज्ञान) के लिए विचारार्थ विषय

- 1. भू-वैज्ञानिक कार्यकलापों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, मजबूत स्थानिक और विशेषता युक्त डेटाबेस के साथ भू-सूचना विज्ञान विकसित करना।
- 2. एनएसडीआई वास्तुकला के तहत सामान्य मानकों और साझा करने योग्य डेटाबेस विकसित करने के लिए भूवैज्ञानिक एजेंसियों के बीच; और समय-समय पर भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति (जीडीपीडीसी) के निर्देशों के अनुरूप समन्वय की सुविधा प्रदान करना और इंटरनेट-आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भूवैज्ञानिक जानकारी के व्यापक और सहज प्रसार को प्रोत्साहित करना।
- 3. राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपॉजिटरी (एनजीडीआर) की समीक्षा करना और हितधारकों से एनजीडीआर में सुधार के लिए सलाह लें।
- 4. आईबीएम द्वारा विकसित किए जा रहे माइनिंग टेनमेंट और रजिस्ट्री सिस्टम के साथ समन्वय करना।
- 5. गुणवत्तापूर्ण और अद्वितीय भू-स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा तक पहुँचने के लिए नीति तैयार करना और सीजीपीबी को सलाह देना।
- 6. 3डी और मॉडलिंग आउटपुट तैयार करने के लिए डोमेन समृद्ध सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से डेटा के परिष्कृत प्रबंधन के लिए नई पद्धतियां विकसित करना।
- 7. जीएसआई पोर्टल के संदर्भ में समिति के कार्यकलाप क्षेत्र से संबंधित अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना।
- 8. समिति के सार्थक विचार-विमर्श के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य संस्थानों को आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल करने की शक्ति समिति के पास होगी।

# समिति XII: सतत विकास के लिए भूविज्ञान

संयोजक: संयुक्त सचिव (नीति), खान मंत्रालय

सदस्य सचिव: निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय

#### सदस्य:

- 1. सलाहकार (टीपीपीसी), खान मंत्रालय
- 2. पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि

- 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि
- 4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि
- 5. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि
- 6. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के प्रतिनिधि
- 7. भूमि संसाधन विभाग के प्रतिनिधि
- 8. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि
- 9. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रतिनिधि
- 10. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रतिनिधि
- 11. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी)
- 12. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
- 13. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
- 14. जीआईएस/स्थानिक डेटा अनुप्रयोग से संबंधित राज्य एजेंसियां (संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित की जाने वाली)

## स्थायी आमंत्रित:-

- सतत विकास से संबंधित मुद्दों से निपटने का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले अखिल भारतीय स्तर के 10 गैर सरकारी संगठनों को उपरोक्त क्रम संख्या 2 से 10 पर मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से नामांकित किया जाना।
- ii. विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, नई दिल्ली
- iii. आईसीएआर-एनबीएसएस एवं एलयूपी
- iv. राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना (एनएसडीआई)
- v. राष्ट्रीय भु-स्थानिक कार्यक्रम प्रभाग (तत्कालीन एनआरडीएमएस)
- vi. स्कूल ऑफ एनवाईरनमेंटल साइंसेस, जे.एन.यू
- vii. भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून
- viii. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद
- ix. ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी)
- x. सीएसआईआर से प्रतिनिधि।

# समिति-XII के लिए सीजीपीबी की समिति के लिए विचारार्थ विषय

# (सतत विकास के लिए भूविज्ञान)

- 1. पर्यावरणीय मुद्दों के लिए नीति निर्माण में भूविज्ञान के एकीकरण की सुविधा प्रदान करना और संकल्पनाओं को नीति निर्माताओं, गैर-सरकारी पर्यावरण एजेंसियों और आम जनता सहित संभावित हित समूहों तक पहुंचाना।
- 2. देश में जीएसआई और अन्य भूवैज्ञानिक संगठनों द्वारा सर्वेक्षण और गवेषण के दौरान एकत्र किए गए भूवैज्ञानिक डेटा के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से सतत विकास योजनाओं (इष्टतम भूमि उपयोग सहित) को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा और कार्यप्रणाली विकसित करने में सहायता करना।
- 3. भूवैज्ञानिक डेटा संग्रह के लिए नए क्षेत्रों, विशेष रूप से भू-आकृति विज्ञान जैसे स्थानिक डेटा को विकसित करके संबंधित नोडल एजेंसियों की सहायता करना ताकि उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों का विश्लेषण करने और सूचित योजना निर्णय लेने में सहायता मिल सके।
- 4. समिति अन्य संस्थानों को आमंत्रिती के रूप में सहयोजित कर सकती है।

Chairman

Member

Member

Member

Member

Members (30)

Members (12)

#### MINISTRY OF MINES

#### RESOLUTION

New Delhi, the 18th August, 2023

- **F. No. M. I-4/1/2021-Mines I.**—In continuation of this Ministry's Resolution No. 4(2)97-M.I dated 12.03.2009 (hereinafter referred to as the principal resolution) and its subsequent resolutions amending the principal resolution vide resolution No 4(2)/97-M-I dated 08.06.2009, No.4(6)/2013-M.I dated 07.05.2013, No.M.I-4/I/2017-Mines-I dated 10.12.2018 and No. M.I-4/1/2019-Mines I dated 17.05.2019 regarding reconstitution of the Central Geological Programming Board (CGPB) and its twelve committees, the following has been decided by the Central Government in the Ministry of Mines, namely:—
- (i) In the principal resolution, for Para 7, the following shall be substituted, namely:—
- "7. It is, therefore, ordered that with immediate effect, the Central Geological Programming Board shall be constituted as follows: —
- (a) Secretary, Ministry of Mines
- (b) Additional Secretary, Ministry of Mines
- (c) Director General, Geological Survey of India
- (d) Joint Secretary (Policy)
- (e) Representatives (not below rank of Joint Secretary) from
  - (i) Ministry of Environment, Forest and Climate Change
  - (ii) Ministry of New and Renewable Energy
  - (iii) Ministry of Earth Sciences
  - (iv) Ministry of Civil Aviation
  - (v) Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
  - (vi) Ministry of Coal
  - (vii) Ministry of Steel
  - (viii) Ministry of Defence
  - (ix) Department of Science & Technology
  - (x) Ministry of Petroleum and Natural Gas
  - (xi) Department of Space
  - (xii) Department of Atomic Energy
- (f) Advisor (Minerals), NITI Aayog
- (g) Heads of Central Organizations from:
  - (i) Central Ground Water Board (CGWB)
  - (ii) Central Water Commission (CWC)
  - (iii) Indian Bureau of Mines (IBM)
  - (iv) Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
  - (v) Coal India Limited (CIL) and its associates
  - (vi) CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research
  - (vii) Central Mine Planning & Design Institute Limited (CMPDI)
  - (viii) The Singareni Collieries Company Limited (SCCL)
  - (ix) NLC India Limited
  - (x) IIT (ISM) Dhanbad
  - (xi) National Geophysical Research Institute (NGRI)
  - (xii) Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG)
  - (xiii) Directorate General of Hydrocarbons (DGH)
  - (xiv) Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
  - (xv) The Keshava Deva Malaviya Institute of Petroleum Exploration (KDMIPE)
  - (xvi) Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMDER)
  - (xvii) Survey of India (SOI)
  - (xviii) Geological Society of India
  - (xix) The Mining, Geological and Metallurgical Institute of India (MGMI India)

- (xx) Central Pollution Control Board (CPCB)
- (xxi) CSIR-National Environmental Engineering Research Institute (NEERI)
- (xxii) National Remote Sensing Centre (NRSC)
- (xxiii) National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR)
- (xxiv) CSIR-National Institute of Oceanography (CSIR-NIO)
- (xxv) Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre
- (JNARDDC), Nagpur, Maharashtra
- (xxvi) National Mineral Exploration Trust (NMET)
- (xxvii) National Disaster Management Authority (NDMA)
- (xxviii) NMDC Limited
- (xxix) MOIL Limited
- (xxx) KIOCL Limited
- (h) Secretaries to the State Governments, Mining and Geology/Industry/Department Members (Directors, Mining & Geology would be Permanent Invitees)
- (i) Representatives of Industry, from organizations, namely:

Members (06)

- (i) Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)
- (ii) Confederation of Indian Industry (CII)
- (iii) Tata Steel
- (iv) Rungta Mines
- (v) Geomysore Services India Pvt. Ltd.
- (vi) Hindustan Zinc Limited (HZL)
- (j) Addl. Director General/Dy. Director General, Geological Survey of India (GSI) Members in charge of Regions, Map & Publication, Information Technology & Training Institute
- (k) Addl. Director General/Dy. Director General, Policy Support System-Planning Member Secretary & Monitoring, Geological Survey of India (GSI)

The Chairman may nominate a special representative of any other organization related to geoscience as a Special Invitee to a meeting of the Board or as a Permanent Invitee to all meetings of the Board."

(ii) In the principal resolution, for the Annexure A, the following Annexure shall be substituted, namely: —

"Annexure A

#### COMPOSITION AND TERMS OF REFERENCE OF THE COMMITTEES

#### Committee I. Ferrous Minerals (Iron, Manganese, Chromite, etc)

**Convenor:** Addl. Director General/Dy. Director General, Geological Survey of India (GSI), Eastern Region (ER), Kolkata

Member Secretary: Director, Policy Support System, Geological Survey of India (GSI), Eastern Region (ER), Kolkata

### Members:

- 1. Ministry of Steel (Director-Tech Level)
- 2. Ministry of Mines, Director (Policy)
- 3. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Director Level)
- 4. DMG, Govt. of Karnataka
- 5. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
- 6. DMG, Govt. of Goa
- 7. DGM, Govt. of Rajasthan
- 8. DGM, Govt. of Maharashtra
- 9. MRD, Govt. of Madhya Pradesh
- 10. DGM, Govt. of Chhattisgarh

- 11. DMG, Govt. of Jharkhand
- 12. DG, Govt. of Orissa
- 13. Indian Bureau of Mines (IBM)
- 14. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
- 15. Tata Iron and Steel Company (TISCO)
- 16. Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)
- 17. National Mineral Exploration Trust (NMET)
- 18. National Mission Head-II. GSI
- 19. Regional Mission Head-II, GSI (Eastern Region & Southern Region)
- 20. Dy. DG of State Units; Directors of GSI associated with the items of Ferrous Group investigations; Director, PSS-P&M-2, GSI, CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### Permanent Invitees: -

- i. NMDC Limited
- ii. Orissa Mining Corporation Ltd. (OMC)
- iii. Jindal Steel and Power Ltd. (JSPL)
- iv. Manganese Ore (India) Ltd. (MOIL)
- v. Steel Authority of India Limited (SAIL)
- vi. United Exploration India Pvt. Ltd.
- vii. Ecomen Laboratories Pvt. Ltd.
- viii. JSW Steel

#### Committee II. Precious Metals & Minerals (Gold, Platinum Group of Elements, Diamond & Precious Stones)

**Convener:** Addl. Director General/ Dy. Director General, Geological Survey of India (GSI), Southern Region (SR), Hyderabad

*Member Secretary:* Director, Policy Support System, Geological Survey of India (GSI), Southern Region(SR), Hyderabad

## Members:

- 1. Director (Mines IV), Ministry of Mines
- 2. Representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)
- 3. DMG, Govt. of Karnataka
- 4. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
- 5. DGM, Govt. of Tamil Nadu
- 6. DGM, Govt. of Maharashtra
- 7. MRD, Govt. of Madhya Pradesh
- 8. DMG, Govt. of Jharkhand
- 9. DG, Govt. of Odisha
- 10. DGM, Govt. of Chhattisgarh
- 11. DGM, Govt. of Uttar Pradesh
- 12. DMG, Govt. of Rajasthan
- 13. Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)
- 14. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
- 15. Indian Bureau of Mines (IBM)
- 16. National Geophysical Research Institute (NGRI)
- 17. Geo Mysore Services (India) Ltd.
- 18. National Mineral Exploration Trust (NMET)
- 19. National Mission Head-II, GSI
- 20. Regional Mission Head-II, GSI (Eastern Region & Central Region)
- 21. Dy.DG of State Units; Directors of GSI associated with the items of Precious Metals & Minerals Group investigations; Director, PSS-P&M-2, GSI, CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### Permanent Invitees: -

- i. Hutti Gold Mines Company Ltd. (HGML)
- ii. Rungta Mines Pvt. Ltd.
- iii. Deccan Gold Mining Ltd.
- iv. Ramgad Mining and Minerals Pvt. Ltd.
- v. NMDC Limited
- vi. Aditya Birla Group (Essel Mining)
- vii. IIT (ISM) Dhanbad
- viii. CSIR-Institute of Minerals and Materials Technology (IMMT), Bhubaneswar, Odisha.
  - ix. Maheshwari Mining Pvt. Ltd (MMPL)
  - x. Geovale Services Pvt. Ltd.
  - xi. Gemcokati Exploration Private Limited.

### Committee III. Non-Ferrous and Strategic Minerals (Basemetal, Tin, Tungsten, Bauxite)

**Convener:** Addl. Director General/ Dy. Director General, Geological Survey of India (GSI), Western Region (WR), Jaipur

Member Secretary: Director, Policy Support System, Geological Survey of India (GSI), Western Region (WR), Jaipur

#### Members:

- 1. Ministry of Mines, Director (Metal-I)
- 2. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
- 3. DMG, Govt. of Rajasthan
- 4. DGM, Govt. of Maharashtra
- 5. DGM, Govt. of Tamil Nadu
- 6. DMG, Govt. of Karnataka
- 7. DG, Govt. of Orissa
- 8. DGM, Govt. of Jharkhand
- 9. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMDER)
- 10. Indian Bureau of Mines (IBM)
- 11. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
- 12. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC), Nagpur, Maharashtra
- 13. The Energy and Resources Institute (TERI)
- 14. National Mineral Exploration Trust (NMET)
- 15. National Mission Head-II, GSI
- 16. Regional Mission Head-II, GSI (Western Region & Central Region)
- 17. Dy.DG of State Units; Directors of GSI associated with the items of Strategic and Non-ferrous investigations; Director, PSS-P&M-2,GSI,CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### Permanent Invitees: -

- i. Defence Research and Development Organisation (DRDO, Hyderabad)
- ii. Hindustan Copper Limited (HCL)
- iii. National Aluminium Company Limited (NALCO)
- iv. Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL, New Delhi)
- v. HINDALCO
- vi. IMMT, Bhubaneshwar
- vii. IREL (India) Limited, Kerala
- viii. Kerala Rare Earths and Minerals Ltd.
- ix. Bhabha Atomic Research Centre (BARC)
- x. Geo Mysore Services India Pvt. Ltd.
- xi. Geovale Services
- xii. Council on Energy, Environment and Water (CEEW)
- xiii. Centre for Social and Economic Progress (CSEP)

xiv. Hindustan Zinc Limited (HZL)

#### Committee IV: Industrial and Fertilizer Minerals

Convener: Addl. Director General/Dy. Director General, Geological Survey of India (GSI), Central Region (CR), Nagpur

Member Secretary: Director, Policy Support System, Geological Survey of India (GSI), Central Region (CR), Nagpur

#### Members:

- 1. Director (Tech.), Ministry of Mines
- 2. Director, Ministry of Fertilizer
- 3. Director, Department of Industry
- 4. DGM, Govt. of Rajasthan
- 5. DGM, Govt. of Uttar Pradesh
- 6. CGM, Govt. of Gujarat
- 7. MRD, Govt. of Madhya Pradesh
- 8. DMG, Govt. of Meghalaya
- 9. DGM, Govt. of Maharashtra
- 10. DGM, Govt. of Jammu & Kashmir
- 11. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
- 12. DMG, Govt. of Karnataka
- 13. DG, Govt. of Odisha
- 14. Geological Wing, Dept. of Industries, Govt. of Himachal Pradesh
- 15. DGM, Govt. of Chhattisgarh
- 16. DGM, Govt. of Assam
- 17. DMG, Govt. of Telangana
- 18. DGM, Uttar Pradesh
- 19. DGM, Rajasthan
- 20. DGM, Bihar
- 21. Indian Bureau of Mines (IBM)
- 22. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
- 23. National Mineral Exploration Trust (NMET)
- 24. National Mission Head-II, GSI
- 25. Regional Mission Head-II, GSI (Southern Region & North Eastern Region)
- 26. Dy.DG of State Units (Rajasthan or Madhya Pradesh); Directors of GSI associated with the items of Industrial and Fertilizer Mineral Group investigations; Director, PSS-P&M-2,GSI,CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### Permanent Invitees: -

- i. Representative of Cement Industry (ACC Limited)
- ii. FCI Aravalli Gypsum and Minerals India Ltd.
- iii. Rajasthan State Mines and Minerals limited (RSMML)
- iv. Ultratech Cement

## Committee V: Energy Minerals & Resources (Coal, Lignite & Geothermal)

**Convener:** Dy. Director General & HoD, Natural Energy Resources (NEnR), M-IIB, Geological Survey of India (GSI), Kolkata

Member Secretary: Director, NEnR, M-IIB, Geological Survey of India (GSI), Kolkata

#### Members:

- 1. Ministry of Coal (Director-Technical level)
- 2. Ministry of Mines (Director-Technical)
- 3. Ministry of New and Renewable Energy (Director-Technical level)
- 4. NITI Aayog (Advisor/Joint Advisor: Power & Energy)
- 5. DGM, Govt. of Maharashtra

- 6. CGM, Govt. of Gujarat
- 7. DGM, Govt. of Rajasthan
- 8. DGM, Govt. of Chhattisgarh
- 9. DMG, Govt. of Jharkhand
- 10. DMM, Govt. of West Bengal
- 11. DG, Govt. of Odisha
- 12. MRD, Govt. of Madhya Pradesh
- 13. DGM, Govt. of Tamil Nadu
- 14. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
- 15. DGM, Govt. of Uttar Pradesh
- 16. DMG, Govt. of Telangana
- 17. DGM, Govt. of Assam
- 18. DMG, Govt. of Meghalaya
- 19. DGM, Govt. of Nagaland
- 20. DGM, Govt. of Arunachal Pradesh
- 21. DGMR, Govt. of Mizoram
- 22. DG, Hydrocarbons
- 23. CSIR-NGRI
- 24. NLC India Limited
- 25. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
- 26. CIL (CMPDIL, Ranchi)
- 27. The Singareni Collieries Company Limited (SCCL)
- 28. CSIR-CIMFR
- 29. The Energy and Resources Institute (TERI)
- 30. National Mineral Exploration Trust (NMET)
- 31. Chief Engineer, CHQ, GSI
- 32. Dy. DG, Policy Support System Planning & Monitoring, GSI
- 33. Dy. DG., Central Chemical Lab, CHQ, GSI
- 34. National Mission Head-II, GSI
- 35. Regional Mission Head-II, GSI (North Eastern Region & Eastern Region)
- 36. Directors of GSI associated with Energy Minerals & Resources (Coal, Lignite & Thermal); Director, PSS-P&M-2, GSI, CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### Permanent Invitees: -

- i. Steel Authority of India Limited (SAIL)
- ii. Tata Steel
- iii. NTPC Limited
- iv. CSIR-NML, Jamshedpur
- v. The Mining, Geological & Metallurgical Institute of India (MGMI)
- vi. Adani Enterprises
- vii. Jindal Steel and Power Limited (JSPL)

# TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEES OF THE CGPB FOR MINERALS (COMMITTEE-I TO COMMITTEE-V)

Committee-I: Ferrous Minerals, Committee-II: Precious Metals & Minerals, Committee-III: Non Ferrous and Strategic Minerals, Committee-IV: Industrial and Fertilizer Minerals and Committee-V: Energy Minerals and Resources Committees of the CGPB were reconstituted with the following terms of reference: -

- 1. To formulate annual and five year plans for regional, detailed and promotional exploration on a national scale.
- To review the work done so far relating to the activity domain of the Committee including the ongoing programs along with the utilization of the budget of promotional exploration schemes sponsored by different Ministries of Government of India.

- 3. To coordinate the exploration work by Government, Public and Private agencies as per the defined plan objectives and priorities.
- 4. To facilitate and promote partnership between Central and State organizations and Public-Private partnership in exploration.
- 5. To prepare status papers, long/short term perspective plans, updating manual of end-users specifications keeping in view progressive advancement of knowledge and technology.
- 6. To prepare and update the database (including status map) of all regional and detailed exploration involving Central, State and private agencies.
- 7. To formulate methodology and act as a nodal agency for data sharing and dissemination.
- To advise government on conservation and optimum utilization of minerals taking into consideration the
  future needs of the country through adoption of scientific mining, ore dressing and beneficiation technology
  in tune with global standards.
- 9. To ensure uploading of the data in the National Geoscience Data Repository (NGDR) as per the Mineral Exploration Reporting Template (MERT) by the CL/ML/ EL holders and other agencies engaged in mineral exploration, as per rule, and monitor its availability in public domain after lock-in period through an identified system.
- 10. To prioritize Research and Development work in the mineral sector related to exploration techniques, modernization of field/sampling equipments and beneficiation.
- 11. To advise Government on human resource development and training of personnel in order to strengthen the manpower of Central and State organizations.

The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

## Committee VI: Marine Geology & Exploration and Coastal Geoscience

Convener: Dy. Director General & HoD, Geological Survey of India (GSI), Marine & Coastal Survey Division (MCSD), Mangaluru

Member Secretary: Director, Policy Support System(PSS), Geological Survey of India (GSI), Marine & Coastal Survey Division (MCSD), Mangaluru

#### Members:

- 1. Ministry of Mines, New Delhi (Director Tech Level)
- 2. Ministry of Earth Sciences, New Delhi (Director Tech Level)
- 3. Department of Science & Technology (DST), New Delhi (Director Tech Level)
- 4. Indian Bureau of Mines (IBM), Nagpur
- 5. Directorate General of Hydrocarbon, New Delhi
- 6. DG, Govt. of Odisha
- 7. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
- 8. DGM, Govt. of Tamil Nadu
- 9. DMG, Govt. of Kerala
- 10. DMG, Govt. of Karnataka
- 11. DGM, Govt. of Maharashtra
- 12. DMG, Govt. of Goa
- 13. CGM, Govt. of Gujarat
- 14. National Centre of Polar & Ocean Research (NCPOR), Goa
- 15. National Institute of Oceanography (NIO), Goa
- 16. Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research (AMDER), Hyderabad
- 17. National Mission Head-IA, GSI
- 18. National Mission Head-II, GSI
- 19. Dy. DG of State Units; Directors of GSI associated with the investigations on Marine Geology & Exploration and Coastal Geoscience; Director, PSS-P&M-1, GSI, CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### <u>Permanent Invitees: -</u>

- i. Shipping Corporation of India (SCI), Mumbai
- ii. Indian Navy (IN), New Delhi
- iii. National Physical Oceanographic Laboratory (NPOL), Cochin
- iv. National Hydrographic Office (NHO), Dehradun

- v. Space Application Centre (SAC), Ahmedabad
- vi. Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), Hyderabad
- vii. National Institute of Ocean Technology (NIOT), Chennai
- viii. Coastal Erosion Directorate, Central Water Commission, New Delhi
- ix. Integrated Coastal and Marine Area Management (ICMAM), Chennai
- x. Geomarine solutions

#### TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE VI (MARINE) OF THE CGPB

- 1. To formulate annual and five year plans on a national scale.
- 2. To review the work done so far relating to the activity domain of the committee including ongoing projects.
- 3. To make concrete suggestions on the various on-going programmes of GSI and other organizations with reference to the Plan objectives;
- 4. To recommend changes, if necessary, in priorities assigned to various items of work. The priorities and sharing of responsibilities between MoM and MoES have to be defined with respect to (a) systematic seabed mapping and regional offshore mineral exploration in Exclusive Economic Zone (EEZ) and also allocated deep sea areas as per mineralization and (b) systematic seabed mapping of the Extended EEZ in future.
- 5. To update the classification of the coastal morphology and digitization of the data with a view to use these data for planning remedial measures for coastal disasters.
- 6. To propose reclassification of offshore data generated by various organizations for data dissemination to various user agencies keeping in view the strategic and classified nature of the offshore data and to work out the modalities of exchanging the same amongst member organizations as well as in the public domain.
- 7. To prepare status papers, long/short term perspective plans and creating end users specifications in view of the new developments in NMP 2019.
- 8. To suggest collaborative programme between GSI and other member organizations and specialized institutions in India and abroad for development of knowledge in marine geosciences.
- 9. To advise on any matter of special significant relating to particular activity domain viz., coastal geoscience, geotechnical parameters, environmental assessment etc. as considered necessary by the Committee.
- 10. The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

#### Committee VII: Airborne Survey & Remote Sensing

**Convener:** Dy. Director General & HoD, Geological Survey of India (GSI), Remote Sensing and Aerial Survey (RSAS), Bengaluru

Member Secretary: Dy. Director General & HoD, Geological Survey of India (GSI), Remote Sensing and Aerial Survey (RSAS), Bengaluru

#### Members:

- 1. Ministry of Mines, New Delhi (Director Tech Level)
- 2. Ministry of Defence (Director Tech Level)
- 3. Indian Bureau of Mines (IBM)
- 4. DGM Govt. of Madhya Pradesh
- 5. DG, Govt. of Odisha
- 6. DMG, Govt. of Rajasthan
- 7. DMG, Govt. of Andhra Pradesh
- 8. DMG, Govt. of Karnataka
- 9. DGM, Govt. of Chhattisgarh
- 10. DGM, Govt. of Maharashtra
- 11. CGM, Govt. of Gujarat
- 12. National Remote Sensing Center (NRSC)
- 13. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
- 14. Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research (AMDER)
- 15. Central Ground Water Board (CGWB)
- 16. DG, Hydrocarbons (DGH), New Delhi
- 17. National Geophysics Research Institute (NGRI)
- 18. All Regional Remote Sensing Service Centres (RRSC-ISRO)
- 19. Orissa Mining Corporation (OMC)

- 20. Hutti Gold Mines Company Limited (HGML)
- 21. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
- 22. Uranium Corporation of India Limited (UCIL)
- 23. M/s Singareni Collieries Co. Ltd., Telangana
- 24. National Mineral Development Corporation (NMDC)
- 25. Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., Bengaluru
- 26. CMPDI. Ranchi
- 27. Axiom Exploration Group Ltd.
- 28. National Mission Head-IB, GSI
- 29. National Mission Head-II, GSI
- 30. Regional Mission Head-I, GSI (Western Region & Southern Region)
- 31. Dy. DG of State Units; Directors of GSI associated with the investigations on Airborne Survey & Remote Sensing; Director (PGRS); Director, PSS-P&M-1, GSI, CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### Permanent Invitees: -

- i. Director General of Civil Aviation (DGCA)
- ii. Geological Society of India
- iii. Indian Institute of Remote Sensing (IIRS), Dehradun
- iv. Karnataka, Gujarat, Rajasthan State (Remote Sensing Centres)
- v. Project Coordinator, ASRS Group (AMD)
- vi. McPhar India
- vii. Sanders Geophysics India Private Limited

# TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE VII (AIRBORNE SURVEY & REMOTE SENSING) OF THE CGPB

- 1. To formulate annual and five year plans on a national scale.
- 2. To review the work done by various organizations so far relating to the activity domain of the committee.
- 3. To make concrete suggestions on the various ongoing programmes of GSI and other organizations with reference to the Plan objectives.
- 4. To develop mutual interaction and collaboration amongst the different organizations with a view to share databases and developing applications for making least use of the information for geoscientific purposes.
- 5. To promote dissemination of aerogeophysical data and maps in the public domain and find out ways to remove restrictions in sharing aerogeophysical data or suggest suitable measures necessary from time to time.
- 6. To review and monitor technological developments in airborne and heliborne remote sensing and suggest new and cutting-edge technology for adoption for survey and mapping, including hyperspectral and gravity mapping.
- 7. To review the prevalent rules/ restrictions of acquisition, processing, utilization, archiving and publication of data accrued through Exploration License (EL).
- 8. To advise the Government on any related matter as the Committee considers necessary.

The Committee shall have the power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

#### Committee VIII: Geology & Mineral Resources of North Eastern Region (NER)

**Convener:** Addl. Director General/ Dy. Director General, Geological Survey of India (GSI), North Eastern Region (NER), Shillong

Member Secretary: Director, Policy Support System (PSS), Geological Survey of India (GSI), North Eastern Region (NER), Shillong

#### Members:

- 1. Director (Technical), Ministry of Mines
- 2. Advisor (Technical Programming Planning Co-ordination), Ministry of Mines
- 3. Representative of NITI Aayog, Govt. of India (Advisor-Mines)
- 4. Representative of MoES, Govt. of India
- 5. Representative of MoEFCC, Govt. of India
- 6. Indian Bureau of Mines (IBM)
- 7. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)

- 8. Central Ground Water Board (CGWB)
- 9. Central Water Commission (CWC)
- 10. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
- 11. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMDER)
- 12. DGM, Government of Arunachal Pradesh
- 13. DGM, Government of Assam
- 14. DCI, Government of Manipur
- 15. DMG, Government of Meghalaya
- 16. DGMR, Government of Mizoram
- 17. DGM, Government of Nagaland
- 18. DIC, Government of Tripura
- 19. DMMG, Government of Sikkim
- 20. Tata Iron & Steel Ltd, Tatanagar
- 21. Central Mine Planning and Design Institute Ltd (CMPDIL)
- 22. Dy. Director General, GSI Training Institute, Hyderabad
- 23. Dy. DG, GSI, NEnR, M-IIB, GSI, Kolkata
- 24. National Mission Head-II, GSI
- 25. Regional Mission Head-II, GSI, NER
- 26. Dy. DG of State Units; Directors of GSI associated with the investigations on Geology & Mineral Resources of NER; Director, PSS-P&M-2, GSI,CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### Permanent Invitees: -

- i. Representative of DONER, Govt. of India (Director level)
- ii. NEC (Advisor, Minerals)
- iii. Brahmaputra Board
- iv. Border Road Organisation
- v. Oil India Limited (OIL)
- vi. NHPC Limited
- vii. NTPC Limited
- viii. North Eastern Electric Power Corporation Limited (NEEPCO)
- ix. North East Institute of Science & Technology (formerly RRL), Jorhat
- x. Representative from Geology Dept., Nagaland University
- xi. Representative from Geology Dept., Manipur University
- xii. Representative from Geology Dept., Guwahati University
- xiii. Representative from Geology Dept., Dibrugarh University
- xiv. Representative from Geology Dept., Tezpur University
- xv. Representative from Geology Dept., Assam University, Silcharxvi. Representative from Geology Dept. Sikkim University, Gangtok
- xvii. Northeastern Hill University, Shillong
- xviii. IIT, Guwahati
- xix. Lafarge India Pvt. Ltd.
- xx. North Eastern Frontier Railway
- xxi. National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL)
- xxii. North Eastern Coal Limited (unit of CIL only)
- xxiii. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
- xxiv. Coal India Limited
- xxv. Star Cement

## TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE VIII (NORTH EASTERN REGION) OF THE CGPB

- 1. To formulate annual and five year plans on a regional scale.
- 2. The Committee to act as a common platform for all participants (Govt., public, private, universities, R&D institutions etc.) in the field of Geoscience activity.
- 3. To monitor and coordinate all earth science related activity in the NER by the different stakeholders, both public and private, for mapping, exploration & exploitation of mineral resources.
- 4. To address all issues related to the fragile ecosystem of the Region in terms of both natural and anthropogenic hazards.
- 5. NER being the hydropower store house of the country with both public and private organizations engaged for its development, the Committee will act as a common platform to deliberate/ resolve all issues particularly directed towards geological surprises and engineering solutions on water resource development.

- 6. To recommend changes, if necessary, in priorities assigned to various items of work.
- 7. To prepare status papers on various emergent issues, long/ short term perspective plans.
- 8. The Committee shall have power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberation of the Committee.

# Committee IX: Geoscientific Investigations (Geotechnical investigation, Natural Hazards, Climate Change, Environmental Geology, Shallow subsurface Geology & Subsurface Hydrology)

Convener: Addl. Director General/ Dy. Director General, Geological Survey of India (GSI), Northern Region (NR), Lucknow

Member Secretary: Director, Policy Support System (PSS), Geological Survey of India (GSI), Northern Region (NR), Lucknow

#### Members:

- 1. Ministry of Mines, (Director Technical)
- 2. Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- 3. Ministry of Earth Sciences, New Delhi
- 4. National Remote Sensing Centre (NRSC), ISRO
- 5. DGM, Government of Jammu & Kashmir
- 6. Geological Wing, Department of Industries, Government of Himachal Pradesh
- 7. Geology & Mining Unit, Government of Uttarakhand
- 8. DGMs of North Eastern States
- 9. National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur
- 10. Central Ground Water Board (CGWB)
- 11. National Mission Head-IV, GSI
- 12. Regional Mission Head-IV, GSI (Northen Region, Southern Region)
- 13. Dy.DGs and Directors of GSI associated with Geoscientific Investigations (Geotechnical investigation, Natural Hazards, Climate Change, Environmental Geology, Shallow Subsurface Geology & Subsurface Hydrology);Director,PSS-P&M-4, GSI,CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### Permanent Invitees: -

- i. National Disaster Management Authority, New Delhi
- ii. National Institute of Hydrology, Roorkee
- iii. Central Electricity Authority (CEA)
- iv. National Hydroelectric Power Corporation (NHPC)
- v. NWDA
- vi. G.B.Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora
- vii. Central Pollution Control Board
- viii. Snow and Avalanche Study Establishment (SASE), Chandigarh
- ix. Department of Civil Engineering, IIT Kanpur
- x. Institute of Seismological Research, Gandhinagar
- xi. SDM/RC, Government of Jammu & Kashmir
- xii. SDM/RC, Government of Himachal Pradesh
- xiii. SDM/RC, Government of Uttarakhand
- xiv. SDM/RC, Government of Northeastern States
- xv. National Institute of Rock Mechanics (NIRM)
- xvi. National Geophysical Research Institute (NGRI)

#### TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE IX (GEOSCIENTIFIC INVESTIGATIONS) OF THE CGPB

- 1. To formulate annual and five year plans on a national scale.
- 2. To advise the Government from time to time on societal issues arising out of natural hazards and to suggest probable preventive/mitigation measures including rehabilitation.
- 3. To monitor and collect data systematically (where possible on a spatial basis) on a large number of parameters relating not only to landslides and earthquakes, but also other public-health and public good issues having a geospatial dimension like Arsenic, Fluorine pollution, etc.
- 4. To review the work done by different organizations including Standing Committee on Geosciences (SC-G) under Planning Committee-Space Applications Management System (PC-SAMS), PM Committee on Climate Change, etc. and to assess their proposals for future work and to identify the gap areas for future course of action in the geoscientific domains under the purview of the Committee.

- Promoting use of the state-of-the-art research in the geo-environmental and natural hazard domains for effective management of the earth system and its resources.
- To enable integration of relevant data sets including spatial data in order to help develop a GIS application for planning, management, prevention, etc. in respect of various geoscientific related events including natural hazards.
- To advise CGPB on any other urgent matter relating to the particular activity domain, as considered necessary by the Committee.
- The Committee is empowered to convene meetings on smaller groups on specialized subject matter with specific agenda.
- The Committee may co-opt other institutions as invitees as and when necessary for fruitful deliberations.

#### Committee X: Fundamental and Multidisciplinary Geoscience

Convener: Addl./Dy. Director General & National Mission Head-IV, Geological Survey of India (GSI), Kolkata

Member Secretary: Director, M-IV, National Centre of Excellence in Geoscience Research (NCEGR), Geological Survey of India (GSI), Kolkata

#### Members:

- 1. Director (Technical), Ministry of Mines, New Delhi
- Representative from Dept. of Science and Technology, Govt. of India 2.
- 3. Oil and Natural Gas Commission, Dehradun
- 4. National Geophysical Research Institute, Hyderabad
- 5. Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun
- 6. Representative of Indian Bureau of Mines
- 7. Representative of Atomic Mineral Directorate of Exploration and Research
- 8. Regional Mission Head-IV, GSI (Northern Region, Eastern Region, Southern Region)
- 9. DDGs and Directors of GSI connected with Mission -IV Laboratories, programmes on Fundamental Geoscience; Dy. Director General, Training Institute; Director, PSS-P&M-4, GSI, CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### Permanent Invitees: -

- i. Representative of CSIR
- ii. Indian Meteorological Department, Delhi
- iii. Representative from Geology Dept., Punjab University
- iv. Representative from Geology Dept., Calcutta University
- Representative from Geology Dept., Anna University v.
- vi. Representative from Geology Dept., Jadavpur University
- vii. Representative from Geology Dept., Delhi University
- viii. Representative from Geology Dept., M.S. Baroda University
- Representative from Geology Dept., Mysore University ix.
- Representative from Geology Dept., Osmania University х.
- Representative from IIT's (Kharagpur, Mumbai, Roorkee) хi. xii. Representative from Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram
- xiii. Representative from Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL, Hyderabad)
- Representative from NCEMP, Allahabad xiv.
- Representative from Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, Lucknow XV.
- xvi. Representative of Indian School of Mines and Applied Geology
- xvii. Representative of NEERI
- xviii. Representative of CGWB
- Representative of Zoological Survey of India xix.
- Representative of Botanical Survey of India XX.
- Representative from Geology Dept., Pondicherry University xxi.
- Representative of National Institute of Oceanography xxii.
- xxiii. Representative from Dept. of Geology, Savitribai Phule University, Pune
- Representative from Earth Sciences IISER Kolkata xxiv.
- Representative from Geological Studies Unit Indian Statistical Institute XXV.
- xxvi. Hindustan Zinc Limited (HZL)
- xxvii. Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (JNARDDC)
- Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL) xviii.

# TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE-X (FUNDAMENTAL AND MULTIDISCIPLINARY GEOSCIENCE) OF THE CGPB

- 1. To promote and prioritize research in the field of fundamental and applied Geoscience (Geology, Geophysics, Geochemistry, Geomatics).
- 2. To encourage better understanding of geological process in the crust and lithosphere, evolution of earth, localization of minerals, etc.
- 3. To review the state of education in Geosciences and make recommendations to improve the quality of geoscientific education particularly at higher levels in order to improve the pool of geoscience talent.
- 4. To review policy relating to Geoscientific research and make recommendations for improving research infrastructure, funding etc; and ensure better mutual coordination between field practices and fundamental research.
- 5. To continuously review global technological advancements in instrumentation (analytical and scientific) and methodologies and recommend state-of-the-art techniques to be adopted, in order to modernize the laboratories, to bring these at par with international standards.
- To facilitate and coordinate sharing of laboratory facilities available with different organizations for optimum use.
- To promote R&D work for evolving new and efficient techniques in the mineral exploration and mining, for locating new mineral resources, value addition, maximizing utilization and conservation of existing natural resources.
- 8. Participation of different organizations in preparation of Standard Reference Material.
- To help improve the geoscientific knowledge within the States and Central institutions by training or other knowledge acquisition measures for the existing personnel both in field and laboratory techniques and to suggest knowledge sets of personnel for the future.
- 10. To focus on the long-term and short-term activity domains and working plans of different organizations.
- 11. Collection, maintenance, preservation and documentation of earth science samples for curatorial, geological and chemical studies and for exhibition and display purposes.

#### Committee XI: Geoinformatics & Data Management

Convener: Addl./Dy. Director General & National Mission Head-III, Geological Survey of India (GSI), Kolkata

Member Secretary: Director (TC), Mission-III, Geological Survey of India (GSI), Kolkata

#### Members:

- 1. Director (Technical), Ministry of Mines
- 2. Indian Bureau of Mines (IBM)
- 3. Mineral Exploration & Consultancy Limited (MECL)
- 4. Ministry of Earth Sciences (MoES)
- 5. Department of Science and Technology (DST) (dealing with geospatial policies and issues)
- 6. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMDER)
- 7. Directorate of Geology and Mining of all States and Union Territories
- 8. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
- 9. Survey of India (SOI)
- 10. National Remote Sensing Centre (NRSC)
- 11. National Geophysical Research Institute (NGRI)
- 12. Central Ground Water Board (CGWB)
- 13. DDGs in-charge of National Geoscience Data Repository(NGDR) and Online Core Business Integration System (OCBIS)
- DDGs and Directors of GSI associated with programmes on Geoinformatics and data management, NGDR; Director PSS-P&M-3, GSI, CHQ, Kolkata; and Director, CGPB Secretariat, DGCO, New Delhi

#### <u>Permanent Invitees: -</u>

- i. DDG (NIC) dealing with GIS
- ii. Technical Director (NIC) Ministry of Mines
- iii. AMD (NIC)
- iv. One representative of each State to be nominated by Secretary (Information Technology) of the State
- v. National Spatial Data Infrastructure (NSDI)

- vi. National Geospatial Programme Division (erstwhile NRDMS)
- vii. India Meteorological Department (IMD)
- viii. National Disaster Management Authority (NDMA)
- ix. Ministry of Home Affairs (MHA)
- x. Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geoinformatics (BISAG-N)
- xi. Maharashtra Remote Sensing Application Centre (MRSAC)

#### TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE XI (GEOINFORMATICS) OF THE CGPB

- 1. To promote use of information technology in geoscientific activity, develop Geoinformatics with a strong spatial and attribute database.
- To facilitate coordination among geoscientific agencies to develop common standards and sharable databases under the NSDI architecture and in line with the directives of Geospatial Data Promotion and Development Committee (GDPDC) from time to time; and encourage wide and easy dissemination of geoscientific information through internet-based technologies.
- To review the National Geoscience Data Repository (NGDR) and take advice from stakeholders for improving NGDR.
- 4. To coordinate with Mining Tenement & Registry System developed by IBM.
- To formulate policy and advice CGPB for providing access to quality and unique geospatial and non-spatial data.
- 6. To develop new methodologies for sophisticated management of data through the use of domain enriched software to produce 3D and modelling out puts.
- 7. To review the work done so far relating to the activity domain of the Committee, with reference to GSI portal.
- 8. The Committee shall have power to co-opt other institutions as invitees as felt necessary for fruitful deliberations of the Committee.

#### Committee XII: Geoscience for Sustainable Development

Convener: Joint Secretary (Policy), Ministry of Mines

Member Secretary: Director (Tech.), Ministry of Mines

#### Members:

- 1. Advisor (TPPC), Ministry of Mines
- 2. Representative of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, MoEFCC
- 3. Representative of the Department of Science & Technology
- 4. Representative of Ministry of Health and Family Welfare
- 5. Representative of Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare
- 6. Representative of Ministry of Rural Development (MoRD)
- 7. Representative of Department of Land Resources
- 8. Representative of Ministry of Housing and Urban Affairs
- 9. Representative of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
- 10. Representative of Ministry of Earth Sciences
- 11. National Environmental Engineering Research Institute (NEERI)
- 12. Indian Bureau of Mines (IBM)
- 13. Central Ground Water Board (CGWB)
- 14. State Agencies dealing with GIS/Spatial data application (to be nominated by respective State Governments)

## Permanent Invitees: -

i. 10 NGOs of all India character having track record of dealing with issues relating to sustainable development to be nominated in consultation with the Ministries/Departments at S. No. 2 to 10

above.

- ii. Centre for Science and Environment, New Delhi
- iii. ICAR-NBSS&LUP
- iv. National Spatial Data Infrastructure (NSDI)
- v. National Geospatial Programme Division (erstwhile NRDMS)
- vi. School of Environment Sciences, JNU
- vii. Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun
- viii. Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad
- ix. The Energy and Resources Institute (TERI)
- x. Representatives from CSIR

# TERMS OF REFERENCE FOR COMMITTEE OF THE CGPB FOR XII (GEOSCIENCE FOR SUSTAINALE DEVELOPMENT)

- 1. To facilitate integration of geoscience into policy making for environmental issues and to transmit the concepts to potential interest groups including policy makers, non-governmental environmental agencies and general public.
- 2. Help develop a framework and methodology for promoting sustainable development strategies (including optimum land use) through best use of geoscientific data gathered in the course of survey and exploration by GSI and other geoscientific organizations in the country.
- Assist nodal agencies concerned by developing new areas for geoscientific data collection, particularly spatial data such as geomorphology to help them analyse ecosystem functions and make informed planning decisions.
- 4. The Committee may co-opt other institutions as invitees."

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.